

समक्ष वी. रामास्वामी, मुख्य न्यायमूर्ति और उजागर सिंह, न्यायमूर्ति

**मैसर्स प्रीस्टोलाइट ऑफ इंडिया लिमिटेड, फ़रीदाबाद, याचिकाकर्ता।**

**बनाम**

**हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी।**

1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 94841

16 दिसंबर 1987.

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948 की XLVI संख्या) - धारा 11(2) - हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1973 की XX संख्या) - धारा 41 - कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए करदाता के रिटर्न-उस पर किए गए मूल्यांकन आदेश- आदेश- चाहे सर्वोत्तम निर्णय पर आधारित हो मूल्यांकन- सी एवं डी प्रपत्रों के गैर-उत्पादन की स्थिति में कर की रियायती दर का दावा करने वाला निर्धारित- निर्धारण प्राधिकारी-क्या प्रपत्र-प्रपत्रों के उत्पादन के लिए धारा 11(2) के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता है-प्रपत्र-क्या मूल्यांकन कार्यवाही के किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है— सी एवं डी फॉर्म के प्रकृति—बताया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न स्वीकार कर लिया गया हो और प्राधिकरण सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो सी और डी फॉर्म एकत्र करने के लिए पंजाब जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम, 1948 की धारा 11 (2) के तहत नोटिस जारी करने का मूल्यांकन प्राधिकारी पर कोई कर्तव्य नहीं था।

**(पैरा 4)**

अभिनिर्धारित किया गया कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा टर्नओवर का कोई भी हिस्सा जोड़ा या घटाया नहीं गया और कंपनी द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रिटर्न स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन आदेश सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन पर आधारित नहीं है या मूल्यांकन आदेश बनाने के लिए सीमा की अवधि का कोई प्रश्न उठता है।

**(पैरा 4)**

अभिनिर्धारित किया गया कि सी और डी फॉर्म या उसकी डुप्लिकेट मूल्यांकन कार्यवाही के किसी भी चरण में मूल्यांकन प्राधिकारी, आयुक्त या न्यायाधिकरण या यहां तक कि उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत की जा सकती है। सी एवं डी फॉर्म का उत्पादन इस अर्थ में अनिवार्य है कि उक्त फॉर्म के उत्पादन के बिना किसी भी मूल्यांकन प्राधिकारी

के लिए कर की रियायती दर देना संभव नहीं है। यह इस अर्थ में निर्देशिका है कि ऐसे प्रपत्र मूल्यांकन कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका, प्रार्थना करते हुए कि:-

(क) विवादित अनुलग्नकों पी/2 और पी/2 (ए), पी/8, पी/4, पी/6 और पी/8 को रद्द करते हुए एक उत्प्रेषण रिट जारी की जाए।

(ख) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, भी जारी की जाए:

(ग) आगे यह प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, माननीय न्यायालय पूर्वगामी पैरा में उल्लिखित परिस्थितियों के मद्देनजर प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष वसूली कार्यवाही पर रोक लगाए।

याचिकाकर्ताओं के वकील आर. पी. साहनी।

## निर्णय

1. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक रिट याचिका है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा, चंडीगढ़ के एक आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। मामला कर निर्धारण वर्ष 1971-72 और 1972-73 के मूल्यांकन से जुड़ा है। आकलन, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में "पंजाब अधिनियम") और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "केंद्रीय अधिनियम") दोनों के तहत किए गए थे। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1971-72 से संबंधित रिटर्न स्वीकार कर लिया। निर्धारण वर्ष 1972-73 के संबंध में, याचिकाकर्ता मैसर्स प्रेस्टोलाइटऑफ इंडिया लिमिटेड, फ़रीदाबाद ("कंपनी") द्वारा दो तिमाहियों के लिए प्रस्तुत रिटर्न मूल्यांकन प्राधिकारी के पास उपलब्ध थी और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। दूसरी दो तिमाहियों के लिए, कंपनी द्वारा यह तर्क दिया गया कि उसने अपना रिटर्न जमा कर दिया है, लेकिन चूंकि वे विभाग के रिकॉर्ड पर नहीं पाए गए, इसलिए मूल्यांकन प्राधिकारी ने ट्रेडिंग खाते के माध्यम

से उसके द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड को स्वीकार कर लिया और विक्रय के संबंध में टर्नओवर निर्धारित किया। इसलिए, अंततः यह एक ऐसा मामला है जहां कंपनी के रिटर्न को मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मूल्यांकन प्राधिकारी ने मूल्यांकन कार्यवाही में सुनवाई के लिए कंपनी को नोटिस जारी किया क्योंकि निर्धारिती ने रियायती दर का दावा किया था। कंपनी अपने वकील के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुई और उसने अभ्यावेदन दिया कि उस समय तक, अग्नि दुर्घटना के कारण, उसके रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे और वह मूल सी और डी फॉर्म प्रस्तुत नहीं कर सकी थी, जिसके आधार पर उसने कर की रियायती दर का दावा किया था। हालाँकि कंपनी ने स्थानीय कर और केंद्रीय कर के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित टर्नओवर पर विवाद नहीं किया, उन्होंने मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष तर्क दिया कि कंपनी कर की रियायती दर की हकदार थी। चूंकि मूल्यांकन प्राधिकारी के पास सी और डी फॉर्म प्रस्तुत किए बिना कर की रियायती दर देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसलिए उसने कंपनी को साक्ष्य या सी और डी फॉर्म की डुप्लिकेट प्रस्तुत करने का समय दिया। मूल्यांकन प्राधिकारी ने उक्त उद्देश्य के लिए कंपनी को 3/4 अवसर दिए, लेकिन उसने डुप्लिकेट रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। चूंकि मूल्यांकन वर्षों की सीमा तेजी से समाप्त हो रही थी, मूल्यांकन प्राधिकारी ने पंजाब अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम के तहत दिनांक 12 दिसंबर, 1978 के दो अलग-अलग आदेशों के तहत, दोनों मूल्यांकन वर्षों 1971-72 और 1972-73 के लिए मूल्यांकन पूरा किया। कंपनी ने संयुक्त उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (ए), रोहतक (जिन्हें "आयुक्त" कहा जाए) के समक्ष 4 अपीलें कीं, 2 राज्य कर के संबंध में और 2 केंद्रीय कर के संबंध में। कमिश्नर के सामने भी कंपनी ने सी और डी फॉर्म पेश नहीं किए। यह तर्क दिया गया था कि रिकॉर्ड आग से नष्ट हो गए थे और इसलिए, वे सी और डी फॉर्म प्रस्तुत नहीं कर सके और मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष मूल्यांकन कार्यवाही अमान्य थी। कंपनी की ओर से आयुक्त के समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान लागू पंजाब अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मूल्यांकन के लिए केवल 5 वर्ष की

अवधि उपलब्ध थी और हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (जिसे "हरियाणा अधिनियम" कहा जाए) के तहत भी जो अब 1971-72 और 1972-73 दोनों मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू थे और मूल्यांकन सीमा से वर्जित थे। आयुक्त ने दोनों दलीलों को खारिज कर दिया और माना कि उनके समक्ष विचाराधीन मामला सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के तहत नहीं था और संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा अवधि का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस सवाल पर कि क्या सी और डी फॉर्म प्रस्तुत किए जा सकते हैं, आयुक्त ने कहा कि यदि कंपनी कर की रियायती दर का दावा करना चाहती है तो उन्हें प्रस्तुत करना होगा। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि कंपनी ने आयुक्त के समक्ष भी सी और डी फॉर्म की मूल या डुप्लिकेट प्रस्तुत नहीं की थी। दोनों अपीलों के खारिज होने के बाद, कंपनी ने सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल, हरियाणा (इसके बाद "ट्रिब्यूनल") में आगे की अपील की। ट्रिब्यूनल ने मूल्यांकन प्राधिकारी और आयुक्त दोनों के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और माना कि यह सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन का मामला नहीं था और इसलिए उसके सामने एकमात्र विवाद यह था कि क्या निर्धारित टर्नओवर पर कर की रियायती दर को बिना सी और डी फॉर्म के अस्वीकार करना था उचित है। ट्रिब्यूनल ने माना कि कंपनी को उक्त रिकॉर्ड पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए कंपनी, पंजाब अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम दोनों के तहत, कर की रियायती दर की हकदार नहीं है, जैसा कि मूल्यांकन वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए लागू था, साथ ही बाद के अधिनियम के तहत भी जो अब लागू है। यदि कानून का प्रश्न उठाया जाता है तो इस न्यायालय को संदर्भित करने का प्रावधान है, लेकिन कंपनी ने उच्च न्यायालय के संदर्भ के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया। हालाँकि, कंपनी ने अपने आदेश की समीक्षा के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष एक आवेदन दायर किया। जिन प्रावधानों के तहत समीक्षा आवेदन दाखिल करना था, वे हरियाणा अधिनियम की धारा 41 थे। यह प्रावधान करता है कि यदि किसी करदाता को कोई नया और महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य मिलता है, जो उचित परिश्रम

के बाद, उसके ज्ञान में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब ऐसा आदेश दिया गया था, या किसी कारण से रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली गलती या त्रुटि है, समीक्षा आवेदन दायर कर सकती है। हमने समीक्षा आवेदन का अध्ययन कर लिया है। हमने पाया है कि कंपनी ने किसी भी नए या महत्वपूर्ण मामले या सबूत पर जोर नहीं दिया है, जो उचित परिश्रम के बाद उसकी जानकारी में नहीं था। वास्तव में, ट्रिब्यूनल ने बताया कि कंपनी ने वही दलीलें उठाईं जो उसने उस समय उठाई थीं जब आयुक्त के समक्ष या उसके समक्ष अपील दायर की गई थी और अंततः उसने पाया कि समीक्षा आवेदन की अनुमति देने के लिए कोई आधार नहीं था और उसने उसे खारिज कर दिया।

(2) ट्रिब्यूनल द्वारा समीक्षा आवेदन को खारिज करने से असंतुष्ट, कंपनी ने फिर से उसी ट्रिब्यूनल के समक्ष दूसरा समीक्षा आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने दूसरे आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह किसी नए मामले पर आधारित नहीं है। ट्रिब्यूनल के विचार में, यह कानून का इरादा नहीं था कि बिना किसी सीमा के पहले के आदेशों की समीक्षा के लिए आगे आवेदन दायर करके कार्यवाही जारी रखी जाए, जैसा कि हरियाणा अधिनियम की धारा 41 के तहत विचार किया गया था और दूसरे समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

3. उक्त आदेश से व्यथित होकर, कंपनी द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है। हालाँकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह रिट याचिका अकेले आकलन वर्ष 1971-72 से संबंधित है।

4. इस याचिका में उठाया गया पहला बिंदु यह है कि कंपनी को पंजाब अधिनियम की धारा 11(2) के तहत या हरियाणा अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत सी और डी फॉर्म की डुप्लिकेट प्रस्तुत करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था। हम इस बिंदु पर कंपनी के विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि मूल्यांकन प्राधिकारी पर सी और डी फॉर्म एकत्र करने के लिए नोटिस जारी करने का कोई कर्तव्य था, जब कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न

स्वीकार कर लिया गया हो और जब आकलन प्राधिकारी सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के आधार पर आगे बढ़ना नहीं चाहते। हालाँकि, तथ्यात्मक रूप से, हम उल्लेख कर सकते हैं कि कंपनी को नोटिस दिया गया था, जैसा कि रिकॉर्ड से देखा गया है। मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष कंपनी का प्रतिनिधित्व उसके वकील द्वारा किया गया था। कंपनी के विद्वान वकील ने मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष सी और डी फॉर्म या उसकी डुप्लिकेट प्रस्तुत करने के लिए समय लिया। हालाँकि, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त उद्देश्य के लिए कंपनी को 3/4 स्थगन दिए गए थे, उसने उक्त रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। इन परिस्थितियों में, मूल्यांकन प्राधिकारी ने महसूस किया कि चूंकि विचाराधीन मूल्यांकन समयबद्ध था, इसलिए वह और इंतजार नहीं कर सकता था और उसने मूल्यांकन आदेश दिए। जैसा कि हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों से देखा जा सकता है, सीमा का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब डीलर द्वारा दाखिल रिटर्न को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और डीलर को, एक नोटिस द्वारा, कोई और जानकारी देने की आवश्यकता होती है और वह थी उसके द्वारा सुसज्जित नहीं की जाती। ऐसे में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन का प्रश्न ही नहीं उठता। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा टर्नओवर का कोई भी हिस्सा जोड़ा या घटाया नहीं गया और कंपनी द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रिटर्न स्वीकार कर लिया गया है। इन परिस्थितियों में, हम यह नहीं मान सकते कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन आदेश सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन पर आधारित है या सीमा की अवधि का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है। हो सकता है कि अधिकारी इस आधार पर आगे बढ़ें कि सी और डी फॉर्म प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह भी सच है कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने कंपनी को कर की रियायती दर देने के लिए सी और डी फॉर्म तैयार करने पर जोर दिया था, लेकिन, जैसा कि अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि ऐसे फॉर्म या उसकी डुप्लिकेट किसी भी स्तर पर प्रस्तुत की जा सकती हैं। मूल्यांकन प्राधिकारी, आयुक्त या न्यायाधिकरण या यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष मूल्यांकन कार्यवाही के समय भी, लेकिन कंपनी ने ऐसे किसी भी चरण में ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया और न ही उसकी स्वीकृति के लिए कहा। ऐसी

परिस्थितियों में, यह तर्क देने का कोई मतलब नहीं है कि सी और डी फॉर्म का उत्पादन अनिवार्य है, इस आधार पर किया गया मूल्यांकन आदेश गलत हैं। यह इस अर्थ में अनिवार्य है कि सी और डी फॉर्म प्रस्तुत किए बिना किसी भी कर निर्धारण प्राधिकारी के लिए कर की रियायती दर देना संभव नहीं है। यह इस अर्थ में निर्देशिका है कि ऐसे प्रपत्र मूल्यांकन कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसलिए, हमें विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

5 उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है और तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**शिवदेव शर्मा**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**अम्बाला, हरियाणा**